

## राजस्थान राजपत्र विशेषांक

#### RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 14 सोमवार, शाके 1941-अगस्त 5, 2019 Sravana 14, Monday, Saka 1941-August 5, 2019

भाग 3 (क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

#### राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयप्र, अगस्त 05, 2019

संख्या एफ.13(25)विशा/विस/2019 :-राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 जैसा कि दिनांक 05 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर, सचिव।

Bill No. 25 of 2019

## THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2019.
  - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956. In section 3 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-
- (i) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the existing expression "fifty five thousand rupees ", the expression "seventy five thousand" shall be substituted;
- (iii) in clause (b), for the existing expression "forty five thousand rupees", the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted;
- (iv) in clause (bb), for the existing expression "ten thousand five hundred rupees", the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted;
- (v) in clause (c), for the existing expression "forty two thousand rupees", the expression "sixty two thousand rupees" shall be substituted; and

- (vi) in clause (d), for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted.
- 3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 4 of the principal Act,-
  - (i) in sub-section (1),-
    - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
    - (b) for the existing expression "fifty five thousand rupees", the expression "eighty five thousand rupees" shall be substituted;
  - (ii) in sub-section (1-A),-
    - (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 1998 (Act No. 4 of 1998)", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
    - (b) for the existing expression "six thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted;
  - (iii) in sub-section (2),-
    - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
    - (b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted;
  - (iv) in sub-section (3),-
    - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
    - (b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted; and
  - (v) in sub-section (4),-
    - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
    - (b) for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted.
- **4.** Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In clause (c) of subsection (3) of section 5 of the principal Act, for the existing expression "ten thousand", the expression "thirty thousand" shall be substituted.
- **5. Amendment of section 7-B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.-** In section 7-B of the principal Act,-
  - (i) in sub-section (1),-
  - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted; and
  - (ii) in sub-section (3),-
  - (a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "seventy thousand rupees" shall be substituted.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the present level of price, the existing salary and sumptuary and other allowances payable to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries appeard to be inadequate. Under these circumstances, it has been considered expedient to increase the salary and sumptuary and other allowances payable to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, and, therefore, necessary amendments in sections 3, 4, 5 and 7-B of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) have been respectively proposed vide clauses 2,3,4 and 5 of the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश। (प्रतिलिपिः संख्या प.2 (40) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषितीः सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3, 4 and 5 of the Bill, if enacted, shall involve a recurring expenditure of about rupees 2,10,00,000/- per annum.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

#### RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

\_\_\_\_

 $\boldsymbol{A}$ 

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

\_\_\_\_\_

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

\_\_\_\_\_

PRAMIL KUMAR MATHUR, **Secretary.** 

#### 2019 का विधेयक सं. 25

# (प्राधिकृत हिन्दी अन्वाद)

# राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
  - (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- **2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-
  - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी:
  - (ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पिचहत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
  - (iii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
  - (iv) खण्ड (खख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
  - (v) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बासठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (vi) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-
  - (i) उप-धारा (1) में,-
    - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
    - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पिचासी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
  - (ii) उप-धारा (1-क) में,-
    - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख से उसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019 से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "छह हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) उप-धारा (2) में,-
  - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी:
- (iv) उप-धारा (3) में,-
  - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (v) उप-धारा (4) में,-
  - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 5. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 7-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,-
  - (i) उप-धारा (1) में,-
    - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
    - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
  - (ii) उप-धारा (3) में,-
    - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
    - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों के वर्तमान स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार तथा अन्य भत्ते अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय वेतन और सत्कार तथा अन्य भत्तों में वृद्धि करना समीचीन समझा गया है, और इसलिए, राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 3, 4, 5 और 7-ख में आवश्यक संशोधन इस विधेयक के क्रमश: खण्ड 2, 3, 4 और 5 द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

> अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश। (प्रतिलिपिः संख्या प.2 (40) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषितीः सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

#### वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3, 4 और 5, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, तो इससे लगभग 2,10,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

#### राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर, सचिव।